सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत

✷ उपचार के दौरान अन्य एक शिक्षक का निधन

डाबुगां 13 नवम्बर (सन्यूस) डाबुगां ब्लाक के दो शिक्षकों का गत दिवस असामयिक निधन हो गया है।

घटना के अनुसार डाबुगां पुलिस थाना अंतर्गत राज्य राज मार्ग क्र. -39 के पीपलगुड़ा चौक के पास गत 11 नवंबर की रात्रि करीब साढ़े सात बजे हुई एक मोटर सायकल दुर्घटना में डाबुगां ब्लाक मुख्यालय अंतर्गत जयंतीनगर निवासी शिक्षक रमेश शबर 34 वर्ष की मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि मृतक शिक्षक डाबुगां ब्लाक के बोरिगांव पंचायत के छेलीबेड़ा गांव स्थित विधालय में पदस्थ थे। घटना दिवस शिक्षक रमेश शबर किसी कार्य से अपनी नई बुलेट मोटर सायकल पर सवार होकर जैपुर गये थे एवं वहां से कार्य निपटाकर वापस डाबुगां लौट रहे थे कि पीपलगुड़ा चौक के पास रात्रि करीब साढ़े सात बजे मोटर सायकल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में शिक्षक रमेश शबर मोटर सायकल से छिटक कर सडक पर गिर गये एवं गंभीर रुप से घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के संबंध में 108 एम्बुलैंस को सूचित करने पर एम्बुलैंस वाहन मौके पर पहुंच कर घायल को उपचारार्थ डाबुगां के सामुदायिक चिकित्सालय में ले गये जहां पर चिकित्सकों ने शिक्षक को मृत घोषित किया।

घटना के संबंध में डाबुगां थाने को सूचित किये जाने पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार सेठी के निर्देशानुसार सहायक निरीक्षक रंक निधि साहू एवं सहायक उप निरीक्षक गणेश पटनायक ने चिकित्सालय पहुंच कर शव को कब्जे में लेने के साथ ही घटनास्थल से मोटर सायकल जब्त कर थाने ले गई है। 12 नवंबर की सुबह शव का पोस्टमार्टम के उपरांत उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। विदित हो कि मृतक शिक्षक के माता पिता की भी गत एक वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। उसके परिजनों में उसकी पत्नी एवं एक तीन वर्षीया पुत्री ही है। मिलनसार शिक्षक रमेश शवर की असामयिक निधन से डाबुगां में शोक छा गया है।

इसी तरह डाबुगां ब्लाक के चचरागुड़ा पंचायत अंतर्गत बाणुआगुड़ा के विधालय में पदस्थ शिक्षक जयंत कुमार माझी 43 वर्ष की भी गत दिवस नवरंगपुर के निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान निधन हो गया है। मृतक शिक्षक की पत्नी श्रीमती चंद्रिका माझी मानिगांव पंचायत के पूर्व सरपंच थी। उनके भी दो संतान हैं।

दोनो शिक्षकों की असामयिक निधन को लेकर डाबुगां ब्लाक शिक्षक संघ की ओर से 12 नवंबर को एक शोकसभा आयोजित कर मृतात्माओं को श्रध्दांजलि दी गई। शोकसभा में डाबुगां के ब्लाक शिक्षाधिकारी प्रशांत कुमार होता, वरिष्ठ लिपिक कैलास सिंह लाल, संकुल समन्वयक रतिकांत नायक संयुक्त शिक्षक संघ के धनसिंह तंती, दिवाकर बारिक आदि शिक्षकगण उपस्थित थे।

मैंने सिंधी समाज पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ उनका अधिकार उनको दिया है- कमलनाथ

भोपाल 13 नवम्बर (ए) मप्र कांग्रेस कमेटी द्वारा हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के उपलक्ष्य में सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का श्यामला हिल्स स्थित उनके बंगले पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवानदेव ईसरानी के नेतृत्व में सिंधी समाज के प्रमुख लोगों ने कमलनाथ की प्रशंसा की। समाज के लोगों द्वारा दिए गए इस सम्मान के बाद कमलनाथ ने सिंधी समुदाय के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने समाज के लोगों पर कोई अहसान नहीं किया हैए बल्कि उनका अधिकार उनको लौटाया है। हम समाज के पुराने इतिहास को बदलें। सिंधी समाज को राजनैतिक नेतृत्व और अधिकार दिलाने कांग्रेस पार्टी समाज के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ सिंधी समाज का झंडा भी विधानसभा में लहराना चाहिए।

सिंधी समाज भी अपने वादे पर कायम रू पंचायत के अध्यक्ष भगवानदेव ईसरानी ने पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जैसे आपने छिंदवाड़ा में काम किया। वही मॉडल आपकी सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लागू हो। जिस तरह आप अपने वादे पर कायम रहे। उसी तरह पूरा सिंधी समाज भी अपने वादे पर कायम है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने सिंधी समाज को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है।इस कारण पूरा सिंधी समाज कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता है।

30 हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन वितरित

डाबुगां 13 नवम्बर (सन्यूस) डाबुगां के जबागुड़ा गांव में गत दिवस नवरंगपुर वन विभाग की ओर से उज्जवला योजना के तहत हितग्राहियों में एल पी जी गैस कनेक्शन वितरित किया गया।

डाबुगां के वनपास लक्ष्मीकांत साहू के तत्वावधान में आयोजित उक्त कार्यक्रम में जबागुड़ा के सरपंच गोवर्ध्दन भत्रा मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे। इस अवसर पर जबागुड़ा वन सुरक्षा समिति के 30 हितग्राहियों को एल पी जी गैस कनेक्शन के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर चूल्हा, रेगुलेटर, गैस पाईप आदि प्रदान किया गया। पापड़ाहांडी के गैस वितरक एजेंसी के कर्मचारियों ने हितग्राहियों को गैस उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को रसोई गैस की उपयोग से जलाऊ लकड़ी की समस्या से निजात मिलने एवं इससे वनों की सुरक्षा होने की बात कही। साथ ही वनों की सुरक्षा से पर्यावरण संतुलन बनाये रखने ग्रामीणों को समझाईश दी। इस मौके पर वन रक्षक प्रकाश सरकार, जबागुड़ा वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लकी माझी, सदस्य कृपादास महुरिया, हरिहर नायक, कृष्णचंद्र पनका आदि उपस्थित थे।

ओडिशा में 2 अरब डॉलर निवेश करेगा आदित्य बिरला समूह

भुवनेश्वर 13 नवम्बर। । आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने ओडिशा में अगले दो सालों में 2 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। बिरला ने मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव में कहाए हमें यहां उच्च विकास की संभावना है। अगले दो सालों में हम 2 अरब डॉलर के निवेश की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बना हुआ है। उन्होंने कहाए कारोबार के अलावा हम यहां वंचित लोगों की भी मदद करेंगे। ओडिशा में हम 5 लाख लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहाए मैं यहां एक निवेशक के रूप में नहीं आया हूंए बल्कि मैं आपका प्रशंसक भी हूं। आदित्य बिरला समूह का ओडिशा से दीर्घकालिक संबंध हैए जो हमारे द्वारा किए गए निवेश से भी परे है। बिरला ने कहाए यह मुख्यमंत्री ;नवीन पटनायकद्ध का नेतृत्व हैए जिसने राज्य को निवेश के हब में तब्दील कर दिया है।

अस्थाई कार्यालय में एक झण्डा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार

भोपाल 13 नवम्बर (ए) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को अस्थाई कार्यालय की अनुमति इस आधार पर दी जा सकेगी की ऐसा कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं खोला जायेगा । अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल के परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में भी नहीं खोला जा सकेगा । उम्मीदवार अपना अस्थाई कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अस्थाई कार्यालय में लगाये जाने वाले झण्डे और बैनर में अभ्यर्थी केवल पार्टी का प्रतीक अथवा फोटोग्राफही लगा सकेगा।

शपथ पत्र में करोड़ों का कर्ज़ छिपाने का आरोप

भोपाल 13 नवम्बर (ए) मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में आपत्तियों का दौर बड़े पैमाने पर सारी प्रदेश भर में चलता रहा सबसे महत्वपूर्ण मामला भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का था। उनके नामांकन पर उनकी शैक्षणिक योग्यता और शपथ पत्र में पत्नी पर कर्ज़ की जानकारी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई हैं। पटवा के नामांकन पर निर्दलीय प्रत्याशी मान सिंह रघुवंशी और रविंद्र साहू ने आपत्ति जताई है अभी इसका निराकरण होना शेष है। इसी तरह अशोकनगर से कांग्रेसी प्रत्याशी जज पाल सिंह जज्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड्डू राम कोरी और तीन निर्दलीय उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक रिकॉर्ड शस्त्र लाइसेंस अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के बारे में आपत्तियों की गई हैं।

पार्टी के दृष्टि पत्र में शामिल होंगे प्रदेश के लोगों के सुझाव - राकेश

✷ समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान में जनता ने दिए 23 लाख से अधिक सुझाव

भोपाल 13 नवम्बर (ए) पार्टी के समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान के प्रति लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है और इस अभियान कि अंतर्गत प्रदेश भर से 23 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को पार्टी के दृष्टि पत्र में शामिल किया जायेगा। यह बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेशसिंह ने सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सोमवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य या देश में लोकतंत्र सही मायने में तभी पूर्ण होता हैए जब सरकार जनता के द्वारा चुनी गयी होए जनता की हो और जनता के हितों में ही काम करे। मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में हमेशा इस बात का ध्यान रखा है। शिवराजसिंह चौहान ने अभी तक जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है वे सब जनता के सुझावों का प्रतिफल हैं। उन्होंने कहा कि शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर अलग.अलग वर्गों की पंचायतें बुलाकर उनकी बेहतरी के लिए सुझाव मांगे। उन सुझावों के आधार पर योजनाएं बनायी और उनका क्रियान्वयन किया। लाड़ली लक्ष्मी योजनाए कन्यादान योजनाए तीर्थदर्शन योजना और संबल जैसी योजनाएं इन्हीं सुझावों का प्रतिफल हैं।

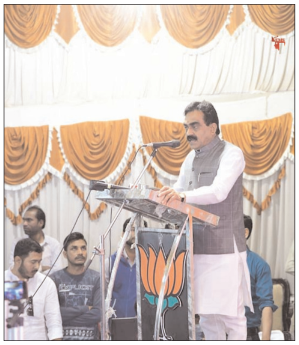

सुझावों से तैयार होगी भविष्य की कल्पना

सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था। 15 वर्षों में अब मध्यप्रदेश तेजी के साथ विकसित होने वाले प्रदेशों की श्रेणी में खडा हुआ है। मध्यप्रदेश आने वाले समय में समृद्ध मध्यप्रदेश के रूप में जाना जायेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 अक्टूबर को समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान शुरू किया था। इस अभियान में 50 हाईटेक रथ रवाना किए गएए जिन्होंने 230 विधानसभाओं में पहुंचकर जनता के सुझाव लिए। प्रत्येक विधानसभा में 20 सुझाव पेटियां लगाई गई थींए जिनके माध्यम से जनता के सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ वेबसाइटए ईमेलए वाट्सअपए एसएमएस एवं मिस कॉल के माध्यम से जनता से सुझाव मांगे थे। प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक यह अभियान पहुंचे इसके लिए कार्यकर्ताओं ने 6 हजार से अधिक स्थानों पर एक चाय एक राय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन सभी माध्यमों से हमें 23 लाख से अधिक महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। इन सारे सुझावों का संकलन कर आने वाले कल की कल्पना तैयार हो रही है। इन सुझावों के माध्यम से आने वाले दिनों में और भी बेहतर योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए और जनता के सामाजिक उत्थान के लिए सामने आएंए ऐसा हमारा प्रयास है। सिंह ने कहा कि इस अभियान के तहत मिले 23 लाख से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को पार्टी के दृष्टि पत्र में शामिल करेंगे।

भेल में पहले दिन 30 फीसदी कर्मचारी लाए मोबाइल

मामला भेल कारखाने में मोबाइल पर प्रतिबंध का

भोपाल ;13 नवम्बर (ए) सुरक्षा कारणों से राजधानी स्थित भेल ;बीएचईएलद्ध कारखाने में मोबाइल पर प्रतिबंध के प्रथम दिन 30 प्रतिशत कर्मचारी मोबाइल लेकर आएए वहीं करीब सत्तर फीसदी कर्मचारी मोबाइल लेकर नहीं आए। सोमवार से कर्मचारियों पर मोबाइल ले जाने में रोक लग गई। वहीं मोबाइल फोन नहीं लाने का भेल की दूसरे नंबर की यूनियन ऑल इंडिया भेल एम्प्लाइज ;एबुद्ध ने विरोध किया। लंच व पारी की समाप्ति के बाद फाउंड्री गेट.5 पर एबु के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कारखाने में मोबाइल फोन ले जाने पर लगाई गई रोक का विरोध किया। इधरए भेल प्रबंधन ने कारखाने की सुरक्षा.व्यवस्था व गोपनीय बातें बाहरी लोगों को पता नहीं चलने के उद्देश्य से मोबाइल पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। वर्तमान में भेल की हैदराबाद यूनिट में मोबाइल ले जाने पर पांबदी है। वहां कर्मचारी काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सिर्फकाम पर ही ध्यान दें।

सुरक्षा.व्यवस्था में सेंध न लगेए इसलिए हैदराबाद यूनिट में मोबाइल पर रोक लगाई गई थी। एबु के मीडिया प्रभारी आशीष सोनी ने बताया कि 50 प्रतिशत भेल कर्मचारी मोबाइल लेकर आए और 50 प्रतिशत नहीं लेकर आए। फाउंड्रीगेट.5 पर मोबाइल पर लगाई गई रोक का विरोध भी किया। हो सकता है कि 70 प्रतिशत लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया हो। क्योंकि कई कर्मचारियों ने लॉकर में मोबाइल रख दिए थे। बीच.बीच में कई कर्मचारी मोबाइल फोन पर मैसेज देखते हुए व कॉल करते हुए दिखे।

युवा इंटक अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि भेल के इतिहास में अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया गया। एक रंग की यूनिफॉर्म होना इस बात से पुष्टि होती है। लेकिनए कुछ दिनों पहले कर्मचारियों पर कारखाने में मोबाइल पर रोक लगा दीए जबकि अधिकारी मोबाइल ले जा सकते हैं। इससे अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया गया है।

शासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रहा

भोपाल 13 नवम्बर (ए) प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि राज्य शासन न सिर्फ चुनाव आयोग के दिशा.निर्देशों की अनदेखी कर रहा हैए बल्कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और चुनाव प्रभावित करने वाले अधिकारियों को जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। यह कार्य आश्चर्यजनक है।

कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में माननीय आयोग के सामने यह तथ्य रखा था कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक एसण्केण् मिश्राए मध्यप्रदेश माध्यम के अधिकारियों का दल बनाकर भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश माध्यम को भाजपा के कार्यालय की तरह उपयोग कर रहे हैं। यहां से मीडिया प्रबंधन कर रहे हैंए विज्ञापन दे रहे हैं। प्रचार सामग्री तैयार कर रहे हैं। प्रायवेट सोशल मीडिया एजेंसी का संचालन कर रहे हैं। आयोग ने संज्ञान लेते हुए संलग्न अधिकारियोंए अपर संचालक जनसंपर्क मंगला मिश्राए उप संचालक जनसंपर्क राजेश बेन और संचालक जनसंपर्क को अन्यत्र पदस्थापना करने के निर्देश दिये थे। आयुक्तए जनसंपर्क ने छह नवम्बर की तारीख में इन दोनों अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए क्रमशः इंदौर एवं सागर संभागीय कार्यालयों से संबद्ध कर दिया है।

गुप्ता ने कहा कि इस आदेश में सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि आचरण संबंधी दोषी अधिकारियों को चुनाव कार्य जैसे संवेदनशील कार्य में जनसंपर्क आयुक्त ने किस आधार पर संबद्ध किया हैघ् इस बात की गारंटी कैसे ली जा सकती है कि ये अधिकारी अपने.अपने कार्य स्थलों पर भाजपा का प्रचार.प्रसार नहीं करेंगेघ्

कांग्रेस ने आयोग से आग्रह किया है कि अशुद्ध आचरण के दोषी इन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर दूर रखना चाहिए। जनसंपर्क आयुक्त को इस प्रकरण की पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में कई संदेहों को पैदा करता है। अतः आयोग से उचित कार्यवाही की अपेक्षा है।

झूठा प्रचार कराकर करोड़ों रुपए की कमाई का अंबानी मॉडल

भोपाल 13 नवम्बर (ए) रिलायंस समूह का पैसा कमाने का तरीका अनोखा और अद्भुत है अक्टूबर 2015 में अनिल अंबानी स्वामित्व की कंपनी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिला उसके पहले ही अगस्त 2015 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से नागपुर में जमीन आवंटन समारोह कराकर रिलायंस समूह ने इसे देशभर में प्रचारित कर दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में पीथमपुर शेज में डिफेंस फैक्ट्री के लिए 400 एकड़ जमीन और हजारों करोड़ों रुपए के निवेश की झूठी खबर मीडिया में प्रसारित करा दी गई इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करके 22 और 23 अक्टूबर 2016 को अनिल अंबानी इन्वेस्टर्स मीट में छाए रहे।

सूचना अधिकार कानून के तहत जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता लगा कि मध्य प्रदेश में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को पीथमपुर में में 400 एकड़ जमीन आवंटित नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई निवेश किया।

इस तरह की झूठी खबरें क्यों मीडिया में फैलाई जाती हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा और प्रयास किया गया तो इन झूठी खबरों के कारण अनिल अंबानी समूह के रिलायंस कंपनी का 1 अक्टूबर 2015 को जो शेयर रुण् 346 का था। 1 अक्टूबर 2016 को रिलायंस का शेयर रुण् 536 पर पहुंच गया। 1 साल में रिलायंस समूह के शेयर में रुण् 190 की वृद्धि हुई जिस में अरबों रुपए का गोलमाल शेयर बाजार के माध्यम से हुआ। रिलायंस समूह में ना तो कोई निवेश किया और ना ही रिलायंस के शेयर करने का कोई कारण था।

राजधानी में बढ़ेगा आईटीएमएस का दायरा

✷ चौक.चौराहों पर लगेंगे दस और कैमरे

भोपाल 13 नवम्बर (ए) राजधानी में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ;आईटीएमएसद्ध का दायरा और बढाया जाएगा। शहर के व्यस्ततम चौक चौराहों पर और दस कैमरे स्थापित किए जाएंगेए ताकि इनकी निगरानी की जा सके। करीब 17 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए आईटीएमएस के लिए वर्तमान शहर में 22 स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। अब 10 अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रमुख मार्गोंए चौराहों व तिराहों का सर्वे किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आईटीएमएस सिस्टम को पूरे शहर की निगरानी के लिए ही तैयार किया गया है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अभी 22 स्थानों पर कैमरे लगाकर इस सिस्टम से काम शुरू किया गया है। देश के जिन शहरों में आईटीएमएस सिस्टम से काम किया जा रहा हैए वहां तीन से चार चरणों में कैमरे की जद में शहर को लाया गया है। इस सिस्टम को तैयार करने वाली दिल्ली की कंपनी मेसर्स टेक्नोसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और यातायात पुलिस को स्थान चिन्हित करने की जवाबदारी सौंपी गई है। 13 जून से अब तक आईटीएमएस सिस्टम ने 35 हजार से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इनमें सर्वाधिक चालान हेलमेट के नियमों के उल्लंघन और जेब्रा लाइन के नियम का पालन नहीं करने वालों के हैं।

इसके अलावा अब चार पहिया वाहनों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहने वालों पर भी चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जो भी वाहन यातायात नियमों को तोड़ते हुए कैमरे में कैद हुए उन्हें आईटीएमएस द्वारा जनरेट हुए चालान भेजे गए हैं। वहीं बार.बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी भी सिस्टम में एकत्र की जाती है। अब तक 35 हजार में से सिर्फ3 हजार 346 लोगों पर ही दोबारा चालानी कार्रवाई हुई है।

वाहन चालकों को ट्रैफिक में फंसना न पड़ेए इसके लिए सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन को हरी झंडी दी जा चुकी है। यातायात पुलिस द्वारा कई सर्वे भी किए गए ए लेकिन मेनुअल नहीं होने के कारण सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। उधरए शहर में आईटीएमएस सिस्टम के कैमरों की संख्या में इजाफा करने के बाद सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन प्रणाली लागू करने में आ रही दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। लिहाजाए जल्द सिस्टम लागू हो सकेगा। बता दें कि सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे वाहन चालकों को चिन्हित स्थानों तक ग्रीन सिग्नल ही मिलेगा। इससे जाम भी नहीं लगता। शहर में अन्य जिलों के वाहन चालक भी यातायात नियमों को तोड़ते हैं। आईटीएमएस की निगरानी के दौरान इनका पूरा ब्यौरा मिल जाता है। इनसे जुर्माना वसूल करने की जिम्मेदारी अन्य जिलों की ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। इसके लिए बाहरी जिलों के वाहन चालकों की सूची तैयार कर भेजी जाती है।

धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की अनुमति नहीं

भोपाल 13 नवम्बर (ए) विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवारों को किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। दलों एवं उम्मीदवारों को लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति में यह ध्यान रखना होगा कि अनुमति की शर्तों का किसी भी तरह उल्लंघन हो।